दैनिक दबंग दुनिया

मुंबई महानगर

डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी ने केंद्रीय बजट 2026 का स्वागत किया; राष्ट्रीय फाइबर योजना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर: आर. सी. खन्ना

वूल एवं वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने दूरदर्शी केंद्रीय बजट 2026 का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप एक सशक्त और दूरगामी रोडमैप बताया है। यह बजट भारत के विनिर्माण आधार को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने तथा वस्त्र क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी ने राष्ट्रीय फाइबर योजना की घोषणा का विशेष रूप से स्वागत किया है, जिसे ऊन, रेशम और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना गया है। यह योजना आयातित कच्चे ऊन पर भारत की निर्भरता को कम करने, गुणवत्तापूर्ण घरेलू रेशों की उपलब्धता बढ़ाने तथा खेत से फैशन तक पूरे ऊन और वूलन मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फाइबर सुरक्षा और एकीकृत क्षेत्रीय विकास पर सरकार का यह फोकस वूलन उद्योग के लिए दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव लाने के साथ-साथ ऊन इकोसिस्टम में सततता, ट्रेसेबिलिटी और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा देगा।श्री आर. सी. खन्ना, अध्यक्ष, डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी ने एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, मेगा टेक्सटाइल पार्कों के विकास तथा समर्थ 2.0 के क्रियान्वयन जैसे उपायों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास और आधुनिकीकरण पर बजट के विशेष जोर का स्वागत किया। ये पहलें वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास तथा रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।अध्यक्ष ने खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए निरंतर नीति समर्थन तथा एमएसएमई और कारीगरों के लिए निर्यात सुविधा उपायों की भी सराहना की। इन पहलों से भारतीय वस्त्र उत्पादों को नए वैश्विक बाजारों तक पहुंच मिलेगी और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी। क्लस्टर आधुनिकीकरण, तकनीक अपनाने और कौशल विकास पर केंद्रित हस्तक्षेपों से उच्च गुणवत्ता एवं सतत वस्त्र उत्पादों के लिए भारत की एक विश्वसनीय सोर्सिंग हब के रूप में स्थिति और मजबूत होने की उम्मीद है।डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी ने वस्त्र क्षेत्र को प्राथमिकता देने तथा भविष्य के लिए तैयार विकास पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी और माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है।परिषद ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्रीय बजट 2026, सततता, नवाचार, निर्यात और समावेशी विकास के संतुलित दृष्टिकोण के साथ, ऊन एवं वस्त्र क्षेत्रों को उल्लेखनीय प्रोत्साहन देगा, जिससे भारत उच्च मूल्य-संवर्धित निर्यात हासिल कर सकेगा और वैश्विक वस्त्र मूल्य शृंखला में अपनी स्थिति को और सुदृढ़ करेगा।

आर. सी. खन्ना
अध्यक्षवूल एवं वूलन एक्सपोर्ट
प्रमोशन काउंसिल

पंजाब केसरी
THU,05 FEBRUARY 2026
EDITION: JALANDHAR, PAGE NO. 7

भारत-अमरीका व्यापार समझौते से वस्त्र एवं ऊनी उत्पादों के निर्यात को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन: आर.सी. खन्ना

नई दिल्ली, 4 फरवरी (विशेष): वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊंसिल ने भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे द्विपक्षीय व्यापार को सशक्त बनाने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है, जिससे भारत के वस्त्र एवं ऊनी उत्पादों के निर्यात को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा।

परिषद ने इस उपलब्धि के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की है, जिनके सतत् कूटनीतिक एवं आर्थिक प्रयासों के परिणामस्वरूप यह समझौता संभव हो सका। इसका स्वागत करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी के अध्यक्ष आर.सी. खन्ना ने कहा कि यह व्यापार समझौता एक विश्वसनीय वैश्विक आर्थिक भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है तथा भारतीय निर्यातकों के लिए अनुकूल बाजार पहुंच सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है।

उन्होंने कहा, "अमरीका द्वारा भारतीय उत्पादों पर शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए निरंतर द्विपक्षीय संवाद का एक सकारात्मक और समयोचित परिणाम है। वस्त्र एवं ऊनी क्षेत्र के लिए यह निर्णय लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा तथा हमारे सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में से एक में पहुंच को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगा। ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन हो रहा है, इस प्रकार के संतुलित व्यापार सुविधा उपाय निर्यातकों और निवेशकों को स्थिरता, पूर्वानुमेयता और नया विश्वास प्रदान करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका भारतीय ऊनी उत्पादों जिनमें परिधान, निटवेयर, शॉल, स्टॉल तथा होम टैक्सटाइल शामिल हैं, के लिए सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। शुल्क में कमी से एक अधिक संतुलित एवं सहायक व्यापार वातावरण निर्मित होने की उम्मीद है, जिससे निर्यात में वृद्धि, उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को और मजबूती मिलेगी।

डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी के उपाध्यक्ष हरमीत सिंह भल्ला ने इस समझौते को दूरदर्शी कदम बताते हुए कहा कि इससे उद्योग, विशेषकर एम.एस.एम.ई. निर्यातकों को दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा, "यह विकास भारत-अमरीका आर्थिक संबंधों की मजबूती को रेखांकित करता है और भारतीय वस्त्र एवं ऊनी निर्यातकों को अमरीकी बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, यह सतत् वस्त्र, मूल्यवर्धित विनिर्माण और डिजाइन-आधारित उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर भी खोलेगा।"

डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के सतत् मार्गदर्शन एवं भारत सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से इस व्यापार समझौते के लाभ निर्यातकों के लिए ठोस परिणामों में परिवर्तित होंगे, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करेंगे तथा वस्त्र एवं ऊनी उत्पादों के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी वैश्विक सोर्सिंग हब के रूप में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ करेंगे।

भारत–अमेरिका ट्रेड डील से वस्त्र एवं ऊनी निर्यात को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन: आर. सी. खन्ना

वूल एंड वूलेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल जी तथा माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण ट्रेड डील की घोषणा के लिए हार्दिक बधाई देता है। यह ट्रेड डील दोनों देशों के बीच गहराते रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को दर्शाती है।इस विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, श्री आर. सी. खन्ना, अध्यक्ष, डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी ने कहा,"भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना द्विपक्षीय संवाद और निरंतर सहभागिता का एक सकारात्मक और समयोचित परिणाम है। यह कदम वस्त्र एवं ऊनी क्षेत्र के लिए लागत प्रतिस्पर्धा को बढ़ाएगा और हमारे सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में से एक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करेगा। ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्मूल्यांकन हो रहा है, इस प्रकार के संतुलित व्यापार सुविधा उपाय निर्यातकों और निवेशकों को स्थिरता, पूर्वानुमेयता और विश्वास प्रदान करते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय ऊनी उत्पादों जैसे परिधान, निटवियर, शॉल, स्टोल्स और होम टेक्सटाइल्स के लिए सबसे बड़े और महत्वपूर्ण गंतव्य बाजारों में से एक है। शुल्क में यह कमी एक अधिक संतुलित और सहायक व्यापार वातावरण तैयार करेगी, जिससे निर्यात को वृद्धि, उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और सुदृढ़ होगी।श्री हरमीत सिंह भल्ला, उपाध्यक्ष, डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी ने कहा कि शुल्क में यह कमी द्विपक्षीय व्यापार संबंधों के प्रति एक व्यावहारिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती है। उन्होंने कहा, "इससे विशेष रूप से एमएसएमई सहित भारतीय वस्त्र एवं ऊनी निर्यातकों को अमेरिका बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने और दीर्घकालिक व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, इससे टिकाऊ वस्त्र, मूल्यवर्धित विनिर्माण और डिजाइन-आधारित उत्पादों जैसे क्षेत्रों में अधिक सहयोग के रास्ते भी खुलेंगे।"डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी भारत सरकार और संबंधित हितधारकों के साथ निरंतर संवाद और सहयोग की आशा करता है, ताकि इस शुल्क कटौती से उत्पन्न लाभ निर्यातकों के लिए ठोस परिणामों में परिवर्तित हो सकें, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती मिले और वस्त्र एवं ऊनी उत्पादों के लिए एक विश्वसनीय वैश्विक सोर्सिंग हब के रूप में भारत की स्थिति और सुदृढ़ हो।डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी देश के दक्षिणी क्षेत्र के निर्यातकों को चर्चगेट चैंबर्स, न्यू मरीन लाइंस, मुंबई स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से निरंतर सेवाएं प्रदान कर रहा है, जहां वस्त्र एवं ऊनी निर्यातकों को सुविधा, मार्गदर्शन और निर्यात संवर्धन सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

नवोदय टाइम्स
Thu,05 February 2026
Edition: main edition, Page no. 9

भारत-अमरीका व्यापार समझौते से वस्त्र एवं ऊनी उत्पादों के निर्यात को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहनः आर.सी. खन्ना

नई दिल्ली, 4 फरवरी (विशेष): वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊंसिल ने भारत और संयुक्त राज्य अमरीका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे द्विपक्षीय व्यापार को सशक्त बनाने वाला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है, जिससे भारत के वस्त्र एवं ऊनी उत्पादों के निर्यात को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा।

परिषद ने इस उपलब्धि के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना की है, जिनके सतत् कूटनीतिक एवं आर्थिक प्रयासों के परिणामस्वरूप यह समझौता संभव हो सका। इसका स्वागत करते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी के अध्यक्ष आर.सी. खन्ना ने कहा कि यह व्यापार समझौता एक विश्वसनीय वैश्विक आर्थिक भागीदार के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा को दर्शाता है तथा भारतीय निर्यातकों के लिए अनुकूल बाजार पहुंच सुनिश्चित करने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है।

उन्होंने कहा, "अमरीका द्वारा भारतीय उत्पादों पर शुल्क को घटाकर 18 प्रतिशत किया जाना प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हुए निरंतर द्विपक्षीय संवाद का एक सकारात्मक और समयोचित परिणाम है। वस्त्र एवं ऊनी क्षेत्र के लिए यह निर्णय लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा तथा हमारे सबसे महत्वपूर्ण निर्यात बाजारों में से एक में पहुंच को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ करेगा। ऐसे समय में जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन हो रहा है, इस प्रकार के संतुलित व्यापार सुविधा उपाय निर्यातकों और निवेशकों को स्थिरता, पूर्वानुमेयता और नया विश्वास प्रदान करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि संयुक्त राज्य अमरीका भारतीय ऊनी उत्पादों जिनमें परिधान, निटवेयर, शॉल, स्टॉल तथा होम टैक्सटाइल शामिल हैं, के लिए सबसे बड़े और महत्वपूर्ण बाजारों में से एक है। शुल्क में कमी से एक अधिक संतुलित एवं सहायक व्यापार वातावरण निर्मित होने की उम्मीद है, जिससे निर्यात में वृद्धि, उत्पाद विविधीकरण को प्रोत्साहन तथा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को और मजबूती मिलेगी।

डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी के उपाध्यक्ष हरमीत सिंह भल्ला ने इस समझौते को दूरदर्शी कदम बताते हुए कहा कि इससे उद्योग, विशेषकर एम.एस.एम.ई. निर्यातकों को दूरगामी लाभ प्राप्त होंगे।

उन्होंने कहा, "यह विकास भारत-अमरीका आर्थिक संबंधों की मजबूती को रेखांकित करता है और भारतीय वस्त्र एवं ऊनी निर्यातकों को अमरीकी बाजार में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, यह सतत् वस्त्र, मूल्यवर्धित विनिर्माण और डिजाइन-आधारित उत्पादों के क्षेत्र में सहयोग के नए अवसर भी खोलेगा।"

डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के सतत् मार्गदर्शन एवं भारत सरकार के साथ घनिष्ठ समन्वय के माध्यम से इस व्यापार समझौते के लाभ निर्यातकों के लिए ठोस परिणामों में परिवर्तित होंगे, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुदृढ़ करेंगे तथा वस्त्र एवं ऊनी उत्पादों के लिए एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी वैश्विक सोर्सिंग हब के रूप में भारत की स्थिति को और सुदृढ़ करेंगे।

India–US Trade Deal to Provide Major Boost to Textile and Woollen Exports: R. C. Khanna

JALANDHAR: Wool & Woollens Export Promotion Council (WWEPC) has hailed the historic trade deal between India and the United States as a landmark achievement that will significantly enhance bilateral trade and provide a major boost to India's textile and woollen exports. The Council has lauded the visionary leadership of the Hon'ble Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for steering this outcome through sustained diplomatic and economic engagement with the United States.

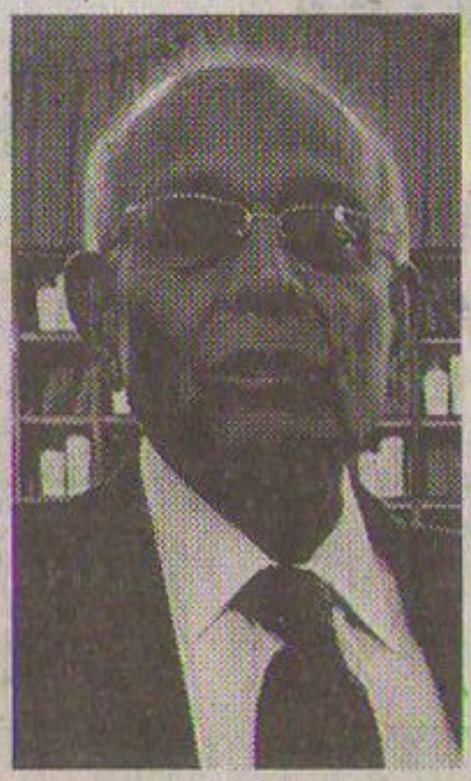

Welcoming the development, Shri R. C. Khanna, Chairman, WWEPC said that the trade deal reflects India's growing stature as a trusted global economic partner and demonstrates the Prime Minister's commitment to securing favourable market access for Indian exporters. "The reduction of US tariffs on Indian products to 18% is a positive and timely outcome of sustained bilateral engagement led by the Hon'ble Prime Minister. For the textile and woollen sector, this measure will enhance cost competitiveness and significantly improve access to one of our most important export markets. At a time when global supply chains are being restructured, such calibrated trade facilitation measures provide stability, predictability, and renewed confidence to exporters and investors," Shri Khanna stated.

He further emphasised that the United States continues to be among the largest and most significant destinations for Indian woollen products, including garments, knitwear, shawls, stoles and home textiles. The tariff reduction is expected to create a more balanced and facilitative trade environment, enabling export growth, encouraging product diversification and strengthening India's integration into global value chains.

अमेरिका के साथ एक नई शुरुआत, ट्रंप ने टैरिफ को 50 से घटाकर 18 प्रतिशत किया

ापीय संघ के साथ
त व्यापार समझौते पर
कुछ ही दिनों के भीतर
थ एक तरह के व्यापार
राम की स्थिति निःसंदेह
द्र मोदी के लिए बड़ी
उनके लिए नए साल की
आत शायद ही हो सकती
से तब जब पिछला साल
व, आपरेशन सिंदूर के
ाशंका और अमेरिका के
नाम रहा। इस संदर्भ में
थ बिगड़ी हुई बात का
कहता है।

ारा भारतीय वस्तुओं पर
टैरिफ को घटाकर 18
का निर्णय मात्र एक
हीं है, बल्कि यह मोदी की
महत्वाकांक्षा और दृढ़ता
जब तमाम विश्लेषक यह
ट्रंप 2.0 के दौर में भारत
ाव और अपमान झेलना
ान मोदी ने धैर्य, रणनीति
ास के साथ स्थिति को
समझौता दर्शाता है कि
क राजनीति में प्रतिक्रिया
बल्कि दिशा तय करने
का है।

देखा जाए तो मोदी ने वह कर दिखाया जो तमाम वैश्विक नेता नहीं कर सके। मोदी ने ट्रंप की कुख्यात 'द आर्ट आफ द डील' रणनीति को समझा और उसे भारत के हित में साध लिया। ट्रंप की सौदेबाजी बेहद आक्रामक, दबाव बनाने वाली और अतिरंजित दावों पर आधारित रही है। कनाडा, यूरोप, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे अमेरिकी सहयोगी भी उनकी इस शैली के सामने अक्सर रक्षात्मक स्थिति में दिखे।

स्वयं भारत ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक सीमित व्यापार समझौते की कोशिश में विफल रहा था, लेकिन इस बार मोदी ने न तो जल्दबाजी दिखाई और न ही आत्मसमर्पण किया। उन्होंने ट्रंप को वह राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि की गुंजाइश दी, जिसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति व्यग्र थे। जबकि वास्तविक लाभ भारत के खाते में गया। यह मोदी की कूटनीतिक परिपक्वता और आत्मविश्वास का प्रमाण है।

टैरिफ कटौती के बीच ट्रंप ने एकतरफा दावे भी किए। जैसे भारत रूसी तेल की खरीद पूरी तरह बंद कर देगा। भारत अमेरिकी उत्पादों की 500 अरब डालर तक की खरीद करेगा और अमेरिकी वस्तुओं पर सभी टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं शून्य कर देगा। ये दावे जितने नाटकीय हैं, उतने ही अव्यावहारिक भी प्रतीत होते हैं। भारत का अमेरिका से कुल वार्षिक आयात करीब 50 अरब डालर से भी कम है। 500 अरब डालर का आंकड़ा नीति से अधिक राजनीतिक नारेबाजी जैसा अधिक है। कृषि जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भारत का पूर्ण उदारीकरण घरेलू राजनीति और सामाजिक स्थिरता के लिहाज से वैसे भी असंभव है। मोदी का इन बिंदुओं पर मौन रहना दर्शाता है कि भारत इस समझौते को एक दिशात्मक संकेत के रूप में देख रहा है, न कि अंतिम और बाध्यकारी समझौते के रूप में। अपने स्वरूप में यह घटनाक्रम किसी ठोस समझौते से अधिक एक राजनीतिक ब्रेकथ्रू है। यह ट्रंप प्रशासन की उसी प्रवृत्ति के अनुरूप है, जिसमें पहले बड़े एलान किए जाते हैं और बाद में विवरण तय होते हैं। अतीत में यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के साथ भी ऐसे 'फ्रेमवर्क समझौतों की घोषणा हुई, जिनका क्रियान्वयन जटिल और लंबा साबित हुआ। भारत-अमेरिका समझौता भी इसी श्रेणी में आता है। इसमें तनाव घटाने, व्यापार बहाली और रणनीतिक खाई को पाटने जैसे लक्ष्य तो स्पष्ट हैं, लेकिन विवरण अभी शेष हैं।

कभी-कभी कूटनीति में दिशा तय करना ही सबसे कठिन कार्य होता है। अमेरिका के दबाव में झुकने के बजाय भारत ने पिछले एक वर्ष में अपने विकल्प भी बढ़ाए। रूस के साथ ऊर्जा सहयोग, चीन के साथ सीमित राजनीतिक संवाद और सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय संघ के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता। इस क्रम में यदि वाशिंगटन भारत के साथ व्यापारिक टकराव जारी रखता तो अमेरिकी कंपनियां दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते बड़े बाजार से बाहर हो जातीं।

यही वह बिंदु है, जिसने अमेरिका को अड़ियल रुख से पीटे हटने को विवश किया। इसमें यूरोपीय संघ के साथ समझौते ने निर्णायक भूमिका निभाई। अमेरिकी रुख में परिवर्तन भारत के लिए भी बड़ी राहत है, क्योंकि उसके 50 प्रतिशत टैरिफ ने भारत को एक बड़े बाजार में सीमित कर दिया था। अमेरिकी टैरिफ का 18 प्रतिशत पर आना न केवल भारतीय निर्यातकों के लिए राहत है, बल्कि यह भारत को फिर से एशियाई प्रतिस्पर्धियों की पंक्ति में खड़ा करता है। इसके चलते वस्त्र, परिधान, रत्न और समुद्री उत्पाद जैसे क्षेत्रों को संजीवनी मिलेगी। चीन से बाहर निकल रही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भारत फिर से एक व्यावहारिक विकल्प बन सकता है। उच्च टैरिफ के चलते जो अवसर भारत के हाथ से फिसल रहे थे, वे फिर से मुट्ठी में आ सकते हैं। अमेरिका के साथ बढ़ती निकटता चीन को भी यह संदेश देगी कि भारत के पास रणनीतिक विकल्प हैं। हालांकि मोदी की विदेश नीति का मूल तत्व अब भी रणनीतिक स्वायत्तता है। यह समझौता उस स्वायत्तता को त्यागने का नहीं, बल्कि उसे मजबूत करने का साधन है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौता एक नई शुरुआत है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं। इसके सामने अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। अवसर इसलिए कि यदि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो भारत-अमेरिका संबंध वास्तव में वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ सकते हैं। चुनौतियां इसलिए कि विवरणों में मतभेद, घरेलू दबाव और ट्रंप की अप्रत्याशित राजनीति इस प्रक्रिया को पटरी से उतार सकती है। इसके बावजूद मोदी को श्रेय देना आवश्यक है। उन्होंने दिखाया कि भारत अब दबाव में झुकने वाला देश नहीं है। यह समझौता मोदी के उस दीर्घकालिक सोच का प्रतीक है, जिसमें भारत को एक आत्मविश्वासी, विकल्पों से भरपूर और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली शक्ति के रूप में स्थापित किया जाना है।

पहले यूरो
बहुप्रतीक्षित मुक्त
मुहर और उसके
अमेरिका के सा
युद्ध में संघर्षवि
प्रधानमंत्री नरेन
उपलब्धियां हैं।
इससे बेहतर शुरु
थी। खास तौर
कूटनीतिक तना
दौरान युद्ध की
साथ खटपट के
अमेरिका के स
बनना बहुत कुछ

अमेरिका द्व
50 प्रतिशत के
प्रतिशत करने
आर्थिक राहत न
विदेश नीति की
की पुष्टि भी है।
मान बैठे थे कि
को लगातार दब
पड़ेगा, उसी दौर
और आत्मविश्व
पलट दिया। यह
भारत अब वैश्वि
देने वाला नहीं,
वाला देश बन चु

India–US trade deal to provide major boost to textile and woolen exports: R C Khanna

JALANDHAR: Wool & Woollens Export Promotion Council (WWEPC) has hailed the historic trade deal between India and the United States as a landmark achievement that will significantly enhance bilateral trade and provide a major boost to India's textile and woollen exports. The Council has lauded the visionary leadership of the Prime Minister of India, Narendra Modi, for steering this outcome through sustained diplomatic and economic engagement with the United States. **BPE**

INDIA–US TARIFF @ 18%

CONGRATULATIONS ON THE SUCCESSFUL CONCLUSION OF INDIA–US TRADE DEAL

"WWEPC expresses its gratitude to the Hon'ble Prime Minister and the Hon'ble Minister of Commerce & Industry and Hon'ble Minister of Textiles for the successful conclusion of the trade agreement with the United States. This landmark agreement reflects visionary leadership, sustained diplomatic engagement, and a strong understanding of India's long-term economic interests. It is expected to significantly strengthen bilateral trade, boost exports, enhance investor confidence and create new opportunities for Indian businesses across sectors, with particular impetus for textile and apparel exports, including woollen products.

Such forward-looking initiatives further reinforce India's position as a trusted global trading partner and will contribute meaningfully to economic growth, employment generation and the overall upliftment of the business ecosystem. WWEPC conveys its sincere appreciation to all stakeholders involved in bringing this important agreement to fruition."

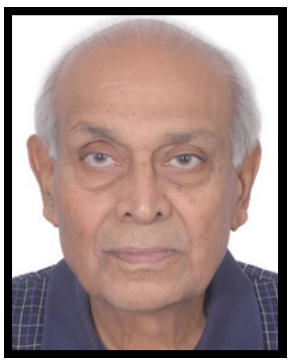

R. C. Khanna
Chairman, WWEPC

बिजनेस वर्ल्ड

राष्ट्रीय फाइबर योजना आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर: आर. सी. खन्ना

हिंदमाता नेटवर्क @ नयी दिल्ली

वूल एवं वूलन एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने दूरदर्शी केंद्रीय बजट 2026 का स्वागत करते हुए इसे विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप एक सशक्त और दूरगामी रोडमैप बताया है। यह बजट भारत के विनिर्माण आधार को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने तथा वस्त्र क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी ने राष्ट्रीय फाइबर योजना की घोषणा का विशेष रूप से स्वागत किया है, जिसे ऊन, रेशम और जूट जैसे प्राकृतिक रेशों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल माना गया है। यह योजना आयातित कच्चे ऊन पर भारत की निर्भरता को कम करने, गुणवत्तापूर्ण घरेलू रेशों की उपलब्धता बढ़ाने तथा खेत से फैशन तक पूरे ऊन और वूलन मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फाइबर सुरक्षा और एकीकृत क्षेत्रीय विकास पर सरकार का यह फोकस वूलन उद्योग के लिए दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव लाने के साथ-साथ ऊन इकोसिस्टम में सततता, ट्रेसबिलिटी और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा देगा। श्री आर. सी. खन्ना, अध्यक्ष, डब्ल्यूडब्ल्यूईपीसी ने एकीकृत वस्त्र कार्यक्रम, मेगा टेक्सटाइल पार्कों के विकास तथा समर्थ 2.0 के क्रियान्वयन जैसे उपायों के माध्यम से क्षेत्रीय विकास और आधुनिकीकरण पर बजट के विशेष जोर का स्वागत किया। ये पहलें वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में अवसंरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल विकास तथा रोजगार सृजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।

शेयर बाजार शुरूआती गिरावट से उबरकर हरे निशान में पहुंचा, सेंसेक्स में 300 अंकों की बढ़त

हिंदमाता नेटवर्क @ मुंबई

UNION BUDGET 2026–27

UNION BUDGET 2026: A STRONG BOOST FOR TEXTILES & MSMES

“The Union Budget 2026 marks an important step towards strengthening India’s textile ecosystem. The strong focus on fibre self-reliance, MSME support, skilling and export facilitation will directly benefit small and medium enterprises, artisans and traditional textile clusters.

Key initiatives such as the National Fibre Scheme and cluster-based interventions will improve raw material availability, enhance cost competitiveness and help Indian woollen and textile products gain greater access and visibility in global markets.

I thank Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Hon’ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman ji and Hon’ble Minister of Textiles Shri Giriraj Singh ji for their continued support and vision for the textile sector.”

Harmeet Singh Bhalla
Vice Chairman, WWEPC

INDIA–EU FTA

WWEPC expresses its sincere gratitude to Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi for his visionary leadership in delivering the India–EU Free Trade Agreement, securing zero-duty access to the European Union.

A GAME CHANGER FOR WOOLLEN TEXTILES

THIS HISTORIC AGREEMENT WILL:

- Boost exports of Indian woollen textiles, shawls, stoles, garments & home furnishings
- Enhance global competitiveness of MSME exporters
- Promote sustainable, value-added textile manufacturing
- Generate employment and deepen global value-chain integration

follow us:
@wwepcindia1

www.wwepcindia.com

WWEPC WELCOMES FORWARD-LOOKING UNION BUDGET 2026: NATIONAL FIBRE SCHEME A MILESTONE FOR SELF-RELIANCE, LAYING STRONG FOUNDATIONS FOR VIKSIT BHARAT 2047

WWEPC welcomes the forward-looking Union Budget 2026, which sets a strong and ambitious foundation for Viksit Bharat 2047. I commend the announcement of the National Fibre Scheme, a much-needed initiative that will boost self-reliance in natural fibres such as wool, silk and jute. This will significantly reduce India's dependence on imported raw wool and strengthen the long-term sustainability of our wool and woollen value chain.

The Budget's focus on sectoral growth through the Integrated Textile Programme, the development of Mega Textile Parks, and the rollout of SAMARTH 2.0 reflects the Government's commitment to modernisation, skilling and value addition. The continued support for khadi, handloom and handicrafts, along with measures to facilitate exports for MSMEs and artisans, will open new avenues for global competitiveness.

I extend my sincere thanks to the Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Hon'ble Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman ji, and the Hon'ble Minister of Textiles Shri Giriraj Singh ji for prioritising the textile sector and strengthening the ecosystem for future growth.

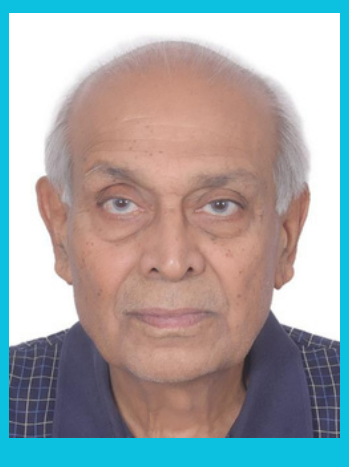

R. C. Khanna
Chairman, WWEPC

INDIA–US TARIFF @ 18%

Thanks and Congratulations to the Hon'ble Prime Minister of India on the Historic India–US Trade Deal

"Heartfelt thanks and congratulations to the Hon'ble Prime Minister of India, the Hon'ble Minister of Commerce & Industry and Hon'ble Textile Minister, on the successful finalisation of the India–US Trade Deal which marks a historic milestone. The deal reduces US tariffs on Indian products to 18%, creating substantial opportunities for India's exports sector. This reduction will act as a strong catalyst for export growth, strengthen bilateral trade ties and reinforce India's position in global value chains, while advancing the India–US economic partnership and supporting India's vision of export-led growth."

Harmeet Singh Bhalla
Vice Chairman, WWEPC

follow us: @wwepcindia1 www.wwepcindia.com

The Only National Textile Daily

Tecoya Trend

VOL. LVI No. 018 MUMBAI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026 PRICE: Rs. 5.00

India-EU FTA levels playing field with competitors: PDEXCIL

MUMBAI, JAN. 29—

The Powerloom Development & Export Promotion Council (PDEXCIL) has welcomed the recently concluded India-EU Free Trade Agreement (FTA), which eliminates tariffs up to 12% on textiles and opens the EU's Euro 263.5 billion import market to Indian powerloom products.

This deal levels the playing field against competitors like Bangladesh and Turkey, enhancing competitiveness for India's decentralized powerloom sector that employs millions in MSME clusters, said Mr. K. Sakthivel, Chairman, PDEXCIL.

PDEXCIL anticipates tripling powerloom exports to EU markets within five years, mirroring UK FTA projections, through technology transfers and joint ventures in technical textiles.

Mr. Sakthivel emphasized: "This FTA fortifies powerloom resilience amid global volatility, positioning small weavers as vital EU partners via preferential access and regulatory alignment."

Powerloom Sector Gains

Powerloom units, producing over 60% of India's fabric, stand to gain from zero-duty access for yarns, cotton fabrics, man-made fibre textiles, and home furnishings key EU imports.

India's textile exports to the EU reached $7.2 billion in recent years, with powerlooms contributing significantly through woven fabrics and made-ups; the FTA could drive further growth by stabilizing orders and boosting capacity utilization in main powerloom clusters like Erode/ Ichalkaranji/Panipat/ Bhiwandi/ Ahemdabad & Surat

Employment and MSME Impact

The agreement supports labor-intensive powerloom MSMEs by enabling scale-up, job creation (textiles employ 45 million directly), and integration into EU supply chains for sustainable, value-added products.

Reduced reliance on imported inputs and easier compliance with EU standards will encourage investments in green manufacturing and machinery upgrades.

FTA - A Historic Game Changer for Woollen Textiles: WWEPC

MUMBAI, JAN. 29—

Wool & Woollens Export Promotion Council (WWEPC) has lauded the Indian government for concluding the India–European Union Free Trade Agreement - the largest and most comprehensive Free Trade Agreement in India's history.

Commenting on the historic development, Mr. R. C. Khanna, Chairman, WWEPC, stated: "The India–EU Free Trade Agreement is a historic achievement and a true game changer for India's

Continued on Page 3

NITMA Welcomes Historic India-EU FTA; says A New Era for Indian Textiles

MUMBAI, JAN. 29—

The Northern India Textile Mills' Association (NITMA), has welcomes the landmark conclusion of negotiations for the India–European Union (EU) Free Trade Agreement (FTA).

"This India–EU FTA could be a game-changer for the Indian textile value chain however its impact will depend on execution, innovation, sustainability, and the industry's ability to deliver value in a demanding market," said Mr. Sidharth Khanna, President of NITMA.

Key benefits for the Textile Sector: The FTA grants zero-duty access across all textile tariff lines, boosting major segments like garments, cotton, and MMF textiles. It will energize 342 districts and key clusters, supporting 45 million livelihoods. Beyond tariff cuts, the pact tackles non-tariff barriers with regulatory cooperation and customs facilitation, while driving investment, technology transfer, and sustainable 'green manufacturing' aligned with EU standards.

Mr. Khanna, advocating for FTA fairness and balance, highlighted a long standing critical duty anomaly in the current India-ASEAN FTA, where raw Polyester Staple Fibre (HS 55032000) faces a 5.5% BCD while finished Polyester Spun Yarn (HS 55092100) enters duty-free. This imbalance has triggered a tenfold surge in imports—rising from 8.4 to 82.7 million kgs, severely disadvantaging Indian mills and prompting NITMA to demand tariff parity across both HSN codes ongoing review of the India-ASEAN FTA, to ensure fair competition.

The India–EU FTA, coupled with recent pacts with the UK, Oman, and New Zealand, solidifies India's status as a premier, sustainable sourcing partner, paving the way for a resilient and inclusive Viksit Bharat.

Industry presses for swift policy action amid tariff pressure: CITI survey

By Our Special Correspondent

MUMBAI, JAN. 29—

Pressure on Indian textile and apparel exporters is intensifying, sharpening industry calls for immediate policy intervention as steep US tariffs begin to translate into lost orders, shrinking margins and accelerated diversion of business to competing sourcing destinations. The second round of an industry survey conducted by the Confederation of Indian Textile Industry captures growing concern across the value chain, with respondents urging faster trade agreements, enhanced export credit support and targeted assistance to offset the erosion of competitiveness in India's largest export market.

At the heart of the disruption is the imposition of an additional 25 percent ad valorem tariff along with a further 25 percent penalty on Indian textile and apparel exports to the US, effectively raising duties by 50 percent. Exporters noted that the tariff escalation has had an immediate impact on buyer behaviour, triggering order reductions, price renegotiations and outright cancellations at a time when global demand remains highly price sensitive.

Against this backdrop, the industry is pressing for swift corrective measures. Respondents have called for expediting free trade agreements with key markets such as the EU-27 and fast-tracking the implementation of the India–UK Comprehensive Economic and Trade Agreement. In parallel, exporters are seeking a higher interest subvention on exports, rising from the current 2.75 percent to 5 percent, along with an extension of collateral-free credit under ECLGS for both MSMEs and large companies. The survey also highlights the need to extend recent relief measures related to loan moratoriums, recalculation of drawing power and credit support at least until 31 March 2026, covering the full textile value chain including Tier-2 and Tier-3 exporters.

The scale of strain is already evident on the ground. Around one-fourth of respondents reported that their turnover declined by more than

Continued on Page 3

THE INTELLIGENT CARD

Next-generation intelligent carding:
The TC 26i

Operator-independent high performance with the only proven T-GO gap optimizer which ensures consistent and optimal carding gaps, resulting in multi-fold increases in quality and productivity levels. Intelligent automation using data from our proven T-CON 3 system.

Up to 2% raw material savings with WASTECONTROL and new generation PMS-2 Precision Mote Knife System for the licker-in.

TRÜTZSCHLER SPINNING

INDIA-EU FTA

INDIA'S BIGGEST FREE TRADE AGREEMENT IN HISTORY

WWEPC proudly acknowledges the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi in delivering the India–European Union Free Trade Agreement, unlocking zero-duty access to one of the world's largest and most premium markets.

WHAT THIS MEANS FOR WOOLLEN SECTOR

- ZERO DUTY MARKET ACCESS FOR INDIAN WOOLLEN TEXTILES, SHAWLS, STOLES, GARMENTS AND HOME FURNISHINGS
- STRONGER GLOBAL COMPETITIVENESS FOR MSME EXPORTERS
- ACCELERATION OF SUSTAINABLE, VALUE-ADDED AND HIGH-QUALITY EXPORTS
- DEEPER INTEGRATION WITH THE EUROPEAN TEXTILE AND FASHION VALUE CHAIN

This historic agreement marks a turning point for India's textile industry—driving export growth, employment generation and global leadership

ZERO-DUTY ACCESS VITAL FOR WOOLLEN & PASHMINA EXPORTS:

INDIA-EU FTA

"India's textile sector is a key driver of exports and employment, with the woollen segment—especially the iconic pashmina shawls—sustaining livelihoods across traditional clusters and MSMEs. Yet, tariff barriers continue to constrain this high-value, employment-intensive sector. As the India–EU Free Trade Agreement nears conclusion, WWEPC urges the Hon'ble Prime Minister to secure comprehensive zero-duty access for woollen products—essential for strengthening pashmina artisans, sustaining jobs and enhancing India's competitiveness in the European Union."

— R. C. Khanna, Chairman, WWEPC —

www.wwepcindia.com

follow us:

@wwepcindia1

Publication Name: Punjab Kesari
Publication Date: 25/01/2026
Edition: Chandigarh
Page No: 11
CCM: 148.41

Demand for Zero Duty Access for Wool and Woolen Products in India-European Union FTA: R.C. Khanna

भारत-यूरोपीय संघ एफ.टी.ए. में ऊन एवं ऊनी उत्पादों को शून्य शुल्क पहुंच दिए जाने की मांग: आर.सी. खन्ना

अमृतसर, 24 जनवरी (स.ह.): भारत का ऊन एवं ऊनी उत्पाद क्षेत्र देश के अनेक

पारंपरिक विनिर्माण क्लस्टरों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) की आजीविका का एक महत्वपूर्ण आधार है। लुधियाना, अमृतसर, पानीपत, श्रीनगर, लेह, कुल्लू, बीकानेर, तिरुपुर, मुंबई सहित देश के विभिन्न भागों में फैले ऊन एवं ऊनी उत्पादों के प्रमुख क्लस्टर इस क्षेत्र की मजबूत आधारशिला हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में यूरोपीय संघ को प्रति वर्ष 50 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का निर्यात करता है।

वूल एंड वूलन्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काऊंसिल (डब्ल्यू.डब्ल्यू.ई.पी.सी.) जो कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत एक निर्यात संवर्धन परिषद है, ने भारत–यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (एफ.टी.ए.) की चल रही वार्ताओं के दौरान ऊन एवं ऊनी उत्पादों के लिए पूर्ण शून्य-शुल्क बाजार पहुंच की निरंतर और सशक्त वकालत की है।

इन शुल्क बाधाओं को हटाए जाने से लुधियाना, अमृतसर, पानीपत, श्रीनगर, लेह, कुल्लू, बीकानेर, तिरुपुर, मुंबई सहित देशभर के पारंपरिक विनिर्माण क्लस्टरों, कारीगरों तथा एम.एस.एम.ई. को उल्लेखनीय प्रोत्साहन मिलेगा और भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय संघ के बाजार में समान अवसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता प्राप्त होगी।

डब्ल्यू.डब्ल्यू.ई.पी.सी. के चेयरमैन आर.सी. खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी, निर्णायक और उद्योग-समर्थक नेतृत्व में भारत सरकार वैश्विक व्यापार मंचों पर भारतीय उद्योगों के हितों की सशक्त और प्रभावी पैरवी कर रही है।

उन्होंने कहा कि ऐसा निर्णय न केवल देश के प्रमुख ऊनी क्लस्टरों को सशक्त करेगा, बल्कि ऊन एवं ऊनी मूल्य श्रृंखला से जुड़े लाखों कारीगरों और एम.एस.एम.ई. की आजीविका को सुरक्षित रखने, सतत् निर्यात को बढ़ावा देने तथा यूरोपीय संघ के बाजार में भारत की उपस्थिति को और मजबूत करने में भी निर्णायक भूमिका निभाएगा।

Summary:

The Indian wool and woolen product sector, a key source of livelihood, seeks zero-tariff access in the India-European Union FTA. The Wool and Woolens Export Promotion Council emphasizes that removing tariff barriers will significantly benefit artisans and MSMEs, enhancing India's presence in the European Union market under Prime Minister Modi's leadership.

INDIA–EU FTA

INDIA'S BIGGEST FTA EVER

WWEPC expresses its sincere gratitude to Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi for his visionary leadership in delivering the India–EU Free Trade Agreement, securing zero-duty access to the European Union.

THIS HISTORIC AGREEMENT WILL:

- Boost exports of Indian woollen textiles, shawls, stoles, garments & home furnishings
- Enhance global competitiveness of MSME exporters
- Promote sustainable, value-added textile manufacturing
- Generate employment and deepen global value-chain integration

follow us: @wwepcindia1

WEBSITE: www.wwepcindia.com

WOOL & WOOLLENS
EXPORT PROMOTION COUNCIL
Ministry of Textiles, Govt. of India

India-Oman CEPA

Big Boost for India's Textile Exports!

The new trade agreement has opened significant export opportunities for India's textile and apparel industry, empowering artisans, weavers, women-led enterprises and MSMEs across the country.

With zero-duty access on 98.08% of Oman's tariff lines, covering 99.38% of India's exports by value, this development will strengthen India's presence in the global textile market.

R. C. Khanna, Chairman, WWEPC

follow us: @wwepcindia1 www.wwepcindia.com

INDIA - UK FTA

A NEW ERA FOR INDIAN WOOLLEN EXPORTS!

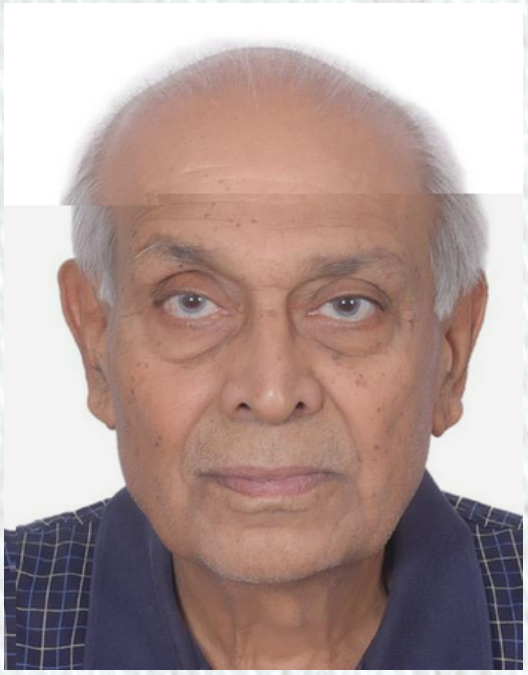

R. C. Khanna
Chairman

The Indian woollen industry thanks Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi and Hon'ble Minister Shri Piyush Goyal for the historic India–UK Trade Agreement—an essential step in boosting exports, creating jobs, and driving economic growth.

With 99% of Indian exports receiving zero-duty access, this agreement opens up vast opportunities for labour-intensive sectors like textiles, particularly woollen industry. Indian exporters will benefit from enhanced market access and competitiveness. This visionary deal reinforces India's commitment to becoming a global manufacturing and services hub.

www.wwepcindia.com